

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भूमिका और परिणामों का अध्ययन

प्रा. कु. एस. आर. शवणकर

राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख

कला वाणज्य महिला महाविद्यालय, बल्लारपुर

प्रस्तावना:

1948 में मानव अधिकार संगठन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की पुष्टि की गई थी। अनुच्छेद 19 (2) कहता है कि सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। उनके अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति को वह जानकारी देने के साथ-साथ सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकता है। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार, 1966, सूचना के अधिकार का भी प्रावधान करता है। **European Covenant on Human Rights, 1996** का अनुच्छेद 10 कहता है कि सभी को राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है; नागरिकों को किसी भी हस्तक्षेप के बिना जानकारी प्राप्त करने और व्यक्त करने का अधिकार है। स्वीडन दुनिया का एकमात्र देश है जिसने 250 साल पहले अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में सूचना के अधिकार को लागू किया था।

भारतीय संसद ने 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया। जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ अनुमोदित किया गया था। साथ ही, 12 अक्टूबर से यह कानून पूरे देश में अस्तित्व में आया। सरकारी काम और प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस कानून को बनाना आवश्यक था। राजस्थान राज्य से सबसे पहले सूचना का अधिकार अधिनियम की माँग शुरू हुई। इसके लिए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अरुणा रॉय के नेतृत्व में लेबर एंड फार्मर्स एसोसिएशन द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया गया था। परिणामस्वरूप, राजस्थान सरकार ने 1 मई, 2000 को कानूनी स्वीकृति दी। लेकिन इसे लागू नहीं कर सके। इसी तरह के कानून मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और असम में बनाए गए थे। यूपीए सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार, सूचना का अधिकार अधिनियम 12 मई 2005 को पारित किया गया था। इसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ-साथ स्थानीय स्वशासी संस्थाओं ने इस कानून को लागू किया। यह कानून भ्रष्टाचार को कम करने में मददगार साबित हो रहा है। इस शोधपत्र का उद्देश्य भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भूमिका और परिणामों का अध्ययन करना है।

अनुसंधान निबंध के लिए प्रयुक्त अनुसंधान विधियाँ:

वर्तमान शोध प्रबंध के लिए उपयोग की जाने वाली जानकारी और तथ्यों को विषय से संबंधित विभिन्न पुस्तकों, पत्रिकाओं, लेखों, समाचार पत्रों से संकलित किया गया है।

अनुसंधान के उद्देश्य:

- 1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भ्रष्टाचार उन्मूलन में कैसे भूमिका निभाता है इसकी खोज करना।
- 2) भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भूमिका का अध्ययन करना।
- 3) भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दोषों एवं परिणामों का अध्ययन करना।
- 4) शोध के निष्कर्षों के आधार पर भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने हेतु एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उचित कार्यान्वयन हेतु सुझाव देना।

अनुसंधान की आवश्यकता और महत्व:

समाज के 60% लोग भ्रष्टाचार का अनुभव करते हैं और शेष 40% लोगों का सरकारी कार्यालयों से कोई संबंध नहीं है। हम भ्रष्टाचार के बढ़ते ज्वार का सामना कर रहे हैं। यह राज्य सरकार के पुलिस विभाग में सबसे अधिक है। उसके बाद अदालतों और जमींदारों का नंबर आता है। आज बिहार भ्रष्टाचार के मामले में सबसे आगे है। केरल में भ्रष्टाचार का स्तर सबसे कम है। बिहार के बाद कर्नाटक, राजस्थान, असम, झारखंड, हरियाणा, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब का स्थान है। महाराष्ट्र इस संबंध में बहुत नीचे है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल भी भ्रष्टाचार से ग्रस्त हैं। भ्रष्टाचार का अंदाजीत वार्षिक आंकड़ा 21068 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इन मामलों का खुलासा किया है। यह सच है कि हमारी अज्ञानता भ्रष्टाचार में वृद्धि का कारण है। इसी लिए 'सूचना अधिनियम' लागू किया गया है। यद्यपि भ्रष्टाचार को मटाना असंभव है, लेकिन निश्चित रूप से इसे कम किया जा सकता है। नागरिकों को इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। सरकार के काम में पारदर्शिता अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके काम से अवगत कराएगी और 'प्रबुद्ध नागरिक' बनाएगी। इस लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उचित कार्यान्वयन और भूमिका को जानना जरूरी है। इस दृष्टिकोण से शोधका विषय महत्वपूर्ण है।

सूचना का अधिकार का अर्थ:

सूचना किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु हो सकती है। जिसमें रिकॉर्ड, ब्रोशर, मेमो, ई-मेल, चर्चा - प्रेस, परिपत्र, आदेश, लिखत दस्तावेज, कागजात शामिल हैं। सूचना इलेक्ट्रॉनिक के साथ-साथ सांख्यिकीय जानकारी आदि के रूप में हो सकती है। जिसे सार्वजनिक कार्यालय द्वारा प्राप्त किया जाता है। सूचना का अधिकार का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र की सेवा में सूचना तक नागरिकों की पहुँच। जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं।

- (1) कार्यों, अभिलेखों, लेखों का निरीक्षण करना।
- (2) किसी भी दस्तावेज या लेख के सत्यापन रिकॉर्ड प्राप्त करना।
- (3) यदि कंप्यूटर और अन्य साधनों के माध्यम से नोटिस लया जा रहा है, तो इसे डस्कट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट या सीडी के साथ-साथ प्रिंटआउट के माध्यम से लया जाना चाहिए।

ऐसे साधनों के माध्यम से सूचना एकत्र करने या साझा करने का अधिकार सूचना का अधिकार है।

कोर्ट की राय में : - भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) C में न केवल भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बल्कि नागरिकों की जानकारी की स्वतंत्रता भी शामिल है। इस लिए, इस खंड के माध्यम से किसी भी देश के नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया गया था। इस अधिकार की सुरक्षा के लिए धारा 19 (1) C है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भूमिका और परिणाम :

इस आंदोलन की शुरुआत भारत में 1990 में हुई जब राजस्थान के एक गैर-सरकारी संगठन मजदूर कसान शक्ति संगठन (MKSS) ने सूखाग्रस्त जिले में कए गए काम और पेट्रोल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लए पहल की। राजस्थान और पंचायत अधिनियम के संशोधन के साथ, पंचायतों को अपने बजट, खातों, व्यय, नीतियों और लाभार्थियों को अपनी योजनाओं के समाचार पत्रों में या होर्डिंग पर प्रकाशित करने के लए मजबूर होना पड़ा। 1990 में मजदूर कसान शक्ति संगठन ने दिल्ली में सूचना के अधिकार के लए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की। इससे पहले, सूचना का अधिकार अधिनियम उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र, प्रेस परिषद और शौरी समिति द्वारा तैयार किया गया था। 2000 के आसपास महाराष्ट्र में अन्ना हजारे के नेतृत्व में आंदोलन ने राज्य सरकार को सूचना का अधिकार अधिनियम पारित करने के लए मजबूर किया। 2004 में सूचना का अधिकार अधिनियम को संशोधित किया गया था। बाद में, महाराष्ट्र के कानून को एक बुनियादी दस्तावेज के रूप में लागू किया गया और केंद्र सरकार द्वारा 'सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005' लागू किया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य:

1) कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर इस अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए। 2) सूचना का अधिकार किसी भी राज्य के व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है लेकिन भारत के अधिकार क्षेत्र में वो आता हो। 3) नागरिकों को आवश्यक जानकारी प्रदान करना। 4) आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक सूचना अधिकारी नियुक्त करना। 5) सूचना का अधिकार एक जागरूक और ज्ञानवान समाज को नागरिक बनने का अधिकार देता है। 6) सूचना के अधिकार के कारण, नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकारी कार्यालयों का काम कैसे किया जाता है। 7) आप अपने आवेदन की जानकारी का दावा कर सकते हैं और अन्य आवेदकों की जानकारी प्राप्त करके इसकी तुलना कर सकते हैं। 8) सूचना प्रदान करने में वफालता के मामले में दंडात्मक प्रावधानों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप जानकारी प्राप्त करने का अधिकार इसमें है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की कार्यप्रणाली का वर्णन:

1) सूचना अधिकारी आवेदक द्वारा कए गए आवेदन के साथ शुल्क स्वीकार करता है। 2) सूचना अधिकारी आवेदन और शुल्क की जाँच करता है। 3) यदि आवश्यक हो तो वह आवेदक को आवेदन लिखने में मदद करता है। 4) सूचना अधिकारी आवेदक को शुल्क और आवेदन की पावती देता है। 5) सूचना अधिकारी यदि आवश्यक हो तो आवेदन या मांग को संबंधित प्राधिकारी को हस्तांतरित करता है। 6) सूचना आवेदन में अगर त्रुटि हो तो सूचना अधिकारी आवेदक को लिखत रूप से सूचित करता है। 7) यदि सूचना अधिकारी सूचना देने से इंकार करता है, तो इसके पीछे का कारण और कतने दिनों के भीतर आदेश के खिलाफ अपील दर्ज की जा सकती है इसकी जानकारी देता है। वह आवेदक को अपीलीय प्राधिकारी के बारे में और अन्य विवरण के बारे में लिखत रूप में सूचित करता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रारूप - 2005 :

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 1 के तहत, अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है। धारा 2 में विभिन्न व्याख्याएं शामिल हैं, जिन्हें निम्नानुसार बताया जा सकता है

2 (c) उपयुक्त शासन - इसमें केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी शामिल है।

2 (e) सक्षम प्राधकारी - इसमें लोकसभा / वधान सभा के अध्यक्ष, राज्यसभा / वधान परिषद के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं।

2 (f) सूचना - इसमें दस्तावेज, टिप्पणियां, ई-मेल, प्रतिक्रिया, सलाह, प्रेस वृत्ति, परिपत्र, आदेश, डायरी, अनुबंध, रिपोर्ट, दस्तावेज प्रपत्र, प्रतिकृतियां, सार्वजनिक प्राधकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध अन्य जानकारी आदि शामिल होते हैं।

2 (g) लोक प्राधकरण - इसमें, संवधान के अनुसार, संसद के अधिनियम के अनुसार, राज्य वधानमंडल के अधिनियम के अनुसार, आदि उपयुक्त सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं।

2 (i) रिकॉर्ड्स में दस्तावेज, पांडुलियां, फाइल माइक्रोफ़िल्म, दस्तावेज प्रतियां, इमेजेस और अन्य कंप्यूटर जनित सामग्री शामिल हैं।

2 (j) सूचना का अधकार - एक सार्वजनिक प्राधकरण द्वारा आयोजित सूचना प्राप्त करने के अधकार में सर्वेक्षण, टिप्पणियां, प्रमाणित प्रतियां, नमूने शामिल हैं। कंप्यूटर आदि में संग्रहीत जानकारी भी शामिल है।

2 (n) तीसरे पक्ष - नागरिकों को छोड़कर सभी प्राधकरण होते हैं। इस अधिनियम के तहत, कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदारी उपयुक्त सरकार के साथ-साथ सार्वजनिक प्राधकारियों पर भी है और निगरानी और नियंत्रण की जिम्मेदारी राज्य / केंद्रीय सूचना आयोग के पास रहती है।

सूचना के अधकार के मूल नियम:

अधिक से अधिक जानकारी देना और अपडेट करना जारी रखें जरूरी है। किसी सार्वजनिक प्राधकरण पर स्वेच्छा से सूचना प्रकाशित करने के लिए कानूनी दायित्व निर्माण करना। शासन में पारदर्शिता और खुलापन निर्माण करना। निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन और अपील पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना। यह नियम जानकारी देने के लिए है, अपवाद जानकारी से इनकार करने के लिए है। नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए एक व्यवहार्य तंत्र विकसित करना। जानकारी के लिए उचित शुल्क लेना जरूरी है। सूचना देखने और नमूने लेने का अधकार है। जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिस उद्देश्य के लिए जानकारी की आवश्यकता है उसका प्रकटीकरण आवेदक के लिए बाध्यकारी नहीं है। अनुरोध के 48 घंटे के भीतर किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता पर जानकारी प्रदान करने का प्रावधान है। सूचना आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है।

सूचना का अधकार अधिनियम का महत्व:

1) देश भर में जागरूक नागरिक और वृद्ध नागरिक संगठन सूचना के अधकार अधिनियम के माध्यम से सरकार को अधिक से अधिक जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2) इस कानून का उपयोग सामाजिक अंकेक्षण का उपयोग करके जमीनी स्तर पर लोगों के लिए सुशासन लाने का एक प्रयास है। 3) इस अधिनियम के माध्यम से जनता में पारदर्शिता, 'जवाबदेही और सार्वजनिक भागीदारी' लाने का प्रयास किया जा रहा है। 4) सूचना के अधकार के कारण, पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक भागीदारी शब्द का नया अर्थ मिला है। सूचना का अधकार अधिनियम गांधीजी की 'ट्रस्टी शिप' की अवधारणा को स्वीकार करता है। इस अवधारणा के अनुसार, शासक सार्वजनिक संस्थानों में जानकारी के मालिक नहीं हैं, बल्कि केवल ट्रस्टी हैं। 5) वैश्विक स्तर पर सूचना के अधकार के मुद्दे को उठाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, सूचित नागरिकों के वृद्ध कार्य समूहों के साथ-साथ मानव अधिकारों के लिए आंदोलन भी महत्वपूर्ण हो गए हैं।

सूचना का अधकार अधिनियम की भूमिका:

आधुनिक युग को लोकतंत्र के युग के रूप में जाना जाता है। उसी समय, लोकतंत्र में, जब लोगों को संप्रभु माना जाता है, तो यह उनका अधिकार है कि वे जानकारी प्राप्त करें जो वे चाहते हैं। जिस तरह वधानमंडल (वधायक) और संसद सदस्य (सांसद) अपनी मनचाही जानकारी के लिए सरकार से सवाल पूछ सकते

हैं। यह उनका विशेष अधिकार माना जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम और बाद में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संबंध में देश भर में कई चर्चाएँ और आंदोलन हुए हैं। स्वीडन ने सबसे पहले 1766 में सूचना का अधिकार कानून लागू किया और आज तक लगभग 60 देशों ने इसे लागू किया है। भारत में, श्रीमती अरुणा रॉय, संभागीय आयुक्त श्री हर्ष मंदार, महाराष्ट्र के वरिष्ठ समाज सुधारक श्री अन्ना हजारे ने सूचना के अधिकार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे देश में, महाराष्ट्र सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2003 लागू किया है ताकि यह साबित हो सके कि यह एक प्रगतिशील राज्य है, जबकि अक्टूबर 2005 को केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया है। परिणामस्वरूप, महाराष्ट्र सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम वापस ले लिया। महाराष्ट्र की तरह ही, RTI अधिनियम को अन्य राज्य सरकारों द्वारा निरस्त कर दिया गया और पूरे भारत में एक समान RTI अधिनियम लागू किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होता है।

यदि कोई नागरिक सरकार से कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो वह इसके लिए पूछ सकता है। एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसे वह जानकारी प्रदान करना भी अनिवार्य होगा। इस कानून ने साबित कर दिया है कि लोग संप्रभु हैं और उन्हें अपनी जरूरत की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। सूचना अधिनियम को भारत की स्वतंत्रता के बाद से अब तक का सबसे क्रांतिकारी कानून माना जाता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विकास में कानून का महत्वपूर्ण स्थान है और पहले कुछ वर्षों में, यह कहा जा सकता है कि RTI ने शासन में कुप्रबंधन पर अंकुश लगा दिया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 की कुछ मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं। (1) सूचना प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को सूचना का अनुरोध करने का अधिकार है। (2) सूचना का अनुरोध करने के लिए व्यक्ति को कारण बताना अनिवार्य नहीं है। (3) एक नमूना आवेदन, उसका संपर्क पता और रुपये का शुल्क। (4) यदि किसी नागरिक ने जीवन की स्वतंत्रता के विषय में जानकारी का अनुरोध किया है, तो वह उसे 48 घंटों के भीतर प्रदान करने के लिए बाध्य है। (5) यदि किसी नागरिक द्वारा सामान्य जानकारी का अनुरोध किया जाता है, तो ऐसी सूचना केवल तीस दिन पहले देना अनिवार्य है। (6) यदि किसी व्यक्ति ने सहायक सूचना अधिकारी को सूचना के लिए आवेदन जमा किया है और आवेदन को प्रधान कार्यालय को भेजना है, तो पांच दिनों की अतिरिक्त अवधि दी जा सकती है। लोक सूचना अधिकारी के निर्णय को तीस दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील की जा सकती है। यदि कोई अधिकारी गलत सूचना देकर गुमराह करता है, तो सार्वजनिक सूचना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। (7) सूचना के अधिकार में कार्य का अवलोकन या निरीक्षण भी शामिल है। (8) सूचना के लिए आवेदन जमा करने के समय से पहले सूचना उपलब्ध कराने में वफादारी के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। (9) अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ सूचना आयुक्त के पास नब्बे दिनों के भीतर अपील दायर की जा सकती है। इस तरह, सूचना के अधिकार की मुख्य विशेषताओं को समझाया जा सकता है और इस अधिकार ने शासन में मनमानी प्रवृत्ति को नियंत्रित किया है।

उत्तर प्रदेश और राज नारायण के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सूचना देना और प्राप्त करना एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवधान लोगों को संपूर्ण जानकारी का अधिकार देता है। यह अधिकार अंतिम नहीं है। इसे कभी-कभी जनहित में रोका जा सकता है। इस अधिनियम के तहत, प्रशासन के पास आदेश, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की नीति है। इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए, सूचना आयुक्त और इसी तरह के पद राज्य और जिला स्तर के साथ-साथ केंद्रीय सूचना आयोग के तहत ब्लॉक स्तर पर स्थापित किए गए हैं। आपको सूचना अधिकारी के पास आवेदन करना होगा गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्तियों से शुल्क नहीं लिया जाता है। इसके लिए धारा 6 और 7 (5) में प्रावधान किया गया है। सूचना अधिकारी को 30 दिनों के भीतर जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। यदि

सूचना जीवन या मृत्यु से संबंधित है, तो ऐसी सूचना 48 घंटों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए। यह धारा (7) (1) में प्रदान किया गया है।

यदि सूचना आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो सूचना अधिकारी संबंधित आवेदक को ऐसा नोटिस देने के लिए बाध्य है। इस कारण से, अस्वीकृति का कारण, कार्यालय, अस्वीकृति का समय और साथ ही सूचना अधिकारी को देना अनिवार्य है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत, न केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को, बल्कि स्थानीय स्व-शासन निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों को भी जानकारी प्रदान करनी होगी। यदि सूचना अधिकारी समयबद्ध तरीके से सूचना देने में सक्षम नहीं है और आवेदक नोटिस से संतुष्ट नहीं है, तो आवेदक इस तरह के आदेश के 30 दिनों के भीतर एक उच्च प्राधिकारी को अपील कर सकता है और केंद्रीय सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी तय कर सकता है कि ऐसी सूचना उचित है या नहीं। आवेदन 30 दिनों के भीतर संसाधित किए जाने हैं। इसकी अधिकतम अवधि 45 दिन तक है। यदि सूचना अधिकारी के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है, या यदि इस तरह के आवेदन को बिना किसी कारण के अस्वीकार कर दिया जाता है, या यदि यह बहुत कम या कोई जानकारी नहीं देता है, तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ सरकारी कार्रवाई की जाती है। एक अधिकारी जो बिना किसी कारण के जानकारी प्रदान करता है, उस पर प्रति दिन 250 रुपये और अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।

कुछ सूचनाओं को इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। क्योंकि यह भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और वैज्ञानिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, इस प्रकार के सूचनाओं को आरटीआई अधिनियम से अलग रखा गया है। राष्ट्रीय हित को खतरे में डालने वाली जानकारी देने के लिए किसी से अनुरोध या आवेदन नहीं किया जा सकता है। यदि कॉपीराइट अधिनियम के उल्लंघन में किसी भी नोटिस या सूचना का अनुरोध किया जाता है, तो वह जानकारी धारा 8 के तहत इस अधिनियम के लिए एक अपवाद होगी, लेकिन इसमें सरकारी कॉपीराइट शामिल नहीं होगा। आवेदक को कारण और व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करना अनिवार्य नहीं है। आपको बस अपना नाम और पता दर्ज करना होगा। सूचना का जो हिस्सा सार्वजनिक किया जाना है, उसका अनुरोध आरटीआई में किया जा सकता है। हालांकि, अगर इसका कुछ हिस्सा ऐसी जानकारी के दायरे में नहीं आता है, तो यह संबंधित प्राधिकरण ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है।

सूचना का अधिकार अधिनियम में दोष:

लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी की जिम्मेदारी है कि वे तय समय के भीतर प्राप्त आवेदन पर जानकारी प्रदान करें या न करें और इसका कारण बताएं। लेकिन कानून ऐसे अधिकारी की सटीक भूमिका को निर्दिष्ट नहीं करता है। एक अधिकारी जो अपनी ड्यूटी करने में वफल रहता है, उसे दंडित किया जाता है, लेकिन अगर वह अधिक गैरजिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार करता है, इस लिए उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है।

निष्कर्ष:

अध्ययन में पाया गया कि, सूचना का अधिकार अधिनियम के उचित कार्यान्वयन और प्रवर्तन से भारत में भ्रष्टाचार और नौकरशाही में बहुत कमी आयी है। यह प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के सद्भाव को भी बना रहा है। इस लिए, भारतीय नागरिकों को स्वयं के माध्यम से मीडिया की स्वतंत्रता में योगदान देना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1923 की सूचना के अधिकार अधिनियम के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम को विकसित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम व्यक्तियों के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा उनको दी गई शक्तियों का लाभ उठाने की कोशिश के रूप में देखा जाता है। इस लए भारत में नौकरशाही का चलन अधिक से अधिक बढ़ा है।

सुझाव:

नागरिकों को सूचना के अधिकार के बारे में बताया जाना चाहिए। यह कानून तभी प्रभावी रूप से काम कर सकता है जब सरकार इस कानून के बारे में देश की जनसंख्या को शिक्षित या शिक्षित करे। भले ही आज भारत में शिक्षा में बहुत प्रगति हो रही है, लेकिन लोगों को ऐसे कानूनों के बारे में जानकारी नहीं है, इस लए उन्हें अपने बीच जागरूकता पैदा करने के लए टीवी, रेडियो, समाचार पत्रों आदि का प्रभावी ढंग से उपयोग करना होगा। साथ ही, प्रशासन में उच्च पदों पर आसीन लोगों को अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से करना चाहिए। यदि इस प्रणाली में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाया जाता है, तो यह कानून लोकतांत्रिक विकास को बढ़ावा देने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

ग्रंथ सूची:

- 1) S. R. Kaneja, A Practical Handbook On Right To Information Act, 2005, The Book Line (1 January 2011)
- 2) P. K. Das, Handbook on the Right to Information Act, 2005, Universal Law Publishing Co Ltd; Edition (1 August 2005)
- 3) एम. लक्ष्मीकांत, भारत की राजव्यवस्था - सवल सेवा एवं अन्य राज्य परीक्षा हेतु, संस्करण प्रथम
- 4) एच. एन. कुशवाहा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ग्रीन लीफ पब्लिकेशन (1 जनवरी 2013)

समाचार पत्र: नवभारत, लोकमत, टाइम्स ऑफ इंडिया

वेबसाइट:

- <https://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf>
- <https://hi.wikipedia.org/wiki/>
- <https://www.nic.in/rti/>